



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 129646

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध ज़मानत अर्ज़ी संख्या - **21048** वर्ष **2026**

नीतू और 2 अन्यआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिवादी

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : पवनकुमार दुबे

प्रतिवादी पार्टी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 71

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

इस ज़मानत अर्ज़ी के ज़रिए, आवेदक नीतू, पुष्पा और आकाश—जो थाना जलालाबाद, ज़िला शाहजहाँपुर के मुकदमा अपराध संख्या 174/2026 (बी.एन.एस. की धारा 312, 313 के तहत) में शामिल हैं—मुकदमे की सुनवाई के दौरान ज़मानत पर रिहा होने की मांग कर रहे हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, संक्षेप में, शिकायतकर्ता एस.आई.यशपाल सिंह ने एफ.आई.आर. में आरोपी-आवेदकों और अन्य सह-आरोपियों के नाम दर्ज कराए हैं। अभियोजन पक्ष की कहानी के मुताबिक, शिकायतकर्ता पुलिस टीम का सदस्य था। एक पुलिस मुखबिर से यह जानकारी मिलने पर कि कुछ आरोपी संपत्ति और कीमती सामान लूटने की योजना बना रहे थे, शिकायतकर्ता पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा और आरोपी-आवेदकों तथा अन्य सह-आरोपियों को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। एफ.आई.आर. में नामजद आरोपी-आवेदकों और अन्य सह-आरोपियों के पास से अलग-अलग

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सामान/धातुएं बरामद की गईं। अभियोजन पक्ष के आरोपों के अनुसार, सभी आरोपी-आवेदक और अन्य सह-आरोपी लूट और अन्य अपराध करने की योजना बना रहे थे।

आवेदकों के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक संख्या 1 और 2, यानी नीतू और पुष्पा, शादीशुदा महिलाएँ हैं, उनके बच्चे हैं जिनकी उन्हें देखभाल करनी है और वे अपने परिवार का घर-गृहस्थी का काम संभाल रही हैं। आरोपी-आवेदकों के जेल में होने के कारण, उनका पूरा परिवार बिखर गया है और बहुत बुरी हालत में है। यह भी कहा गया है कि आरोपी-आवेदकों से कोई भी आग्नेयास्त्र (हथियार) बरामद नहीं हुआ है। आवेदक संख्या...

आवेदक 1 पर दो आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड है, जबकि आवेदक 2 और 3 में से प्रत्येक पर एक-एक आपराधिक मामला दर्ज है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि पुलिस बरामद सामान को किसी भी घटना से नहीं जोड़ पाई, सिवाय एक मामले के, जिसे बाद में गैर-कानूनी तरीके से दूसरी घटना से जोड़ दिया गया। अंत में, आवेदकों के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदकों के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक 02.05.2026 से जेल में बंद हैं और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

इसके उलट, राज्य की ओर से पेश विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का जोरदार विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी हैं और आमतौर पर उन गाड़ियों में लूटपाट करते हैं जिनमें वे यात्री के तौर पर सफ़र करते हैं। पुलिस ने उन्हें लूट की योजना बनाते समय ही रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से पीले और सफ़ेद रंग की धातुएँ बरामद हुई हैं, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और मामले की पूरी तरह से जांच करने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आरोपी-आवेदकों को तब गिरफ्तार किया गया था जब वे लूट की योजना बना रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उनके पास से पीले और सफ़ेद रंग की धातुएँ बरामद की गई हैं। हालाँकि, पुलिस बरामद की गई इन चीज़ों को सह-आरोपियों के अलावा किसी और घटना से नहीं जोड़ पाई है। जिन धाराओं के तहत आरोपी-आवेदकों पर आरोप लगाए गए हैं, उन पर मजिस्ट्रेट की न्यायालय में सुनवाई हो सकती है और उनमें अधिकतम सज़ा सात साल से कम है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, सबूतों, आरोपी की संलिप्तता और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस नतीजे पर पहुंची है कि आवेदकों का जमानत का मामला बनता है। इसलिए, जमानत की अर्जी मंजूर की जाती है।

आवेदकों, यानी नीतू, पुष्पा और आकाश को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का पर्सनल बॉन्ड और दो-दो जमानतदार पेश करने पर, ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या वाले मामले में जमानत पर रिहा किया जाए। यह रिहाई न्याय के हित में लगाई जा रही निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

(i) आवेदक मुकदमे की सुनवाई को जल्द पूरा करने में सहयोग करेंगे और जब तक कोई जरूरी वजह न हो, वे नियमित रूप से न्यायालय में पेश होंगे।

(ii) आवेदक मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देंगे, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे बातें बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

(iv) जमानत देने वालों की पहचान, हैमियत और पते के सबूत की पुष्टि संबंधित न्यायालय करेगी।

ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय को जमानत रद्द करने का अधिकार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत अर्जी पर फैसला करने के मकसद तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। ट्रायल न्यायालय पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष निकालने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगा।

30 जून, 2026

शुभम

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"